प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES
GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय सुधार

1. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना
2. ई-ऑफिस
3. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को कम करना

मासिक रिपोर्ट | फरवरी 2026

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषयसूची

1. मुख्य- मुख्य बातें- फरवरी, 2026.....01

I.ई ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन.....01

II.स्वच्छता अभियान की उपलब्धियाँ (फरवरी, 2026).....02

III.लंबित मामलों में कमी.....02

2. औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग).....03

2.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (फरवरी, 2026).....03

2.2 डिलेयरिंग की स्थिति (फरवरी, 2026).....04

3. ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन.....06

3.1 ई-ऑफिस विश्लेषण.....06

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी.....07

3.3. ई-फाइल सृजन(फरवरी, 2026).....08

3.4. अंतर विभागीय फ़ाइल संचलन.....08

3.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर).....09

3.6. ई-ऑफिस विश्लेषण.....10

4. विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना.....14

4.1. कुल अर्जित राजस्व.....14

4.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (फरवरी,2026) 15

4.3. खाली हुआ स्थान (फरवरी, 2026) 15

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व..................16

4.4. स्वच्छता अभियान स्थल (फरवरी, 2026) 17

4.5. छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (फरवरी, 2026) ....….17

5. पहले- बाद में..…..18

6. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ- कार्यालय स्थान का विस्तार...….20

7. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन...21

8. इन फोकस: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग..23

8.1. कार्यालय स्थान का कुशल प्रबंधन..23

8.2. कचरा निपटान..…...24

8.3 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ...….24

8.4 निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना...…..….25

8.5 उल्लेखनीय उपलब्धियां- फरवरी, 2026..26

9. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन...…....27

10.सरकार में लंबित मामलों के निपटान पर कार्यालय ज्ञापन..…28

11.ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन...…..29

अनुलग्नक I : अपलोड नहीं किए गए आँकड़े..…..31

अनुलग्नक II: संकेताक्षरों की सूची..…..32

1 मुख्य-मुख्य बातें फरवरी, 2026

I. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

66

मंत्रालयों/विभागों के पास ई-फाइलों का कम से कम 90 प्रतिशत हिस्सा है

16

मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रिसीट्स हैं

33

मंत्रालयों/विभागों का औसत ट्रांजैक्शन स्तर 4 या 4 से कम है

ई-फाइलों का उपयोग (%)

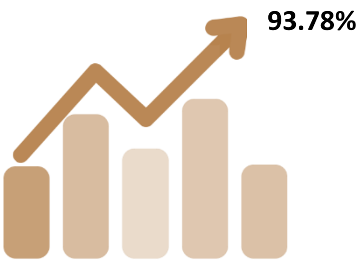

फरवरी 2026: 5,45,988 रिसीट्स में से 5,20,322 ई-रिसीट्स थीं

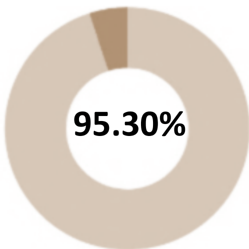

औसत ट्रांजैक्शन स्तर

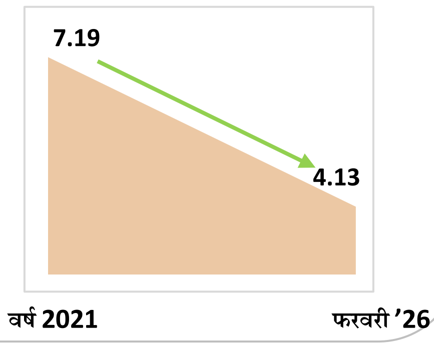

सक्रिय,बंद की गई और कुल ई-फ़ाइलों के मासिक आँकड़े

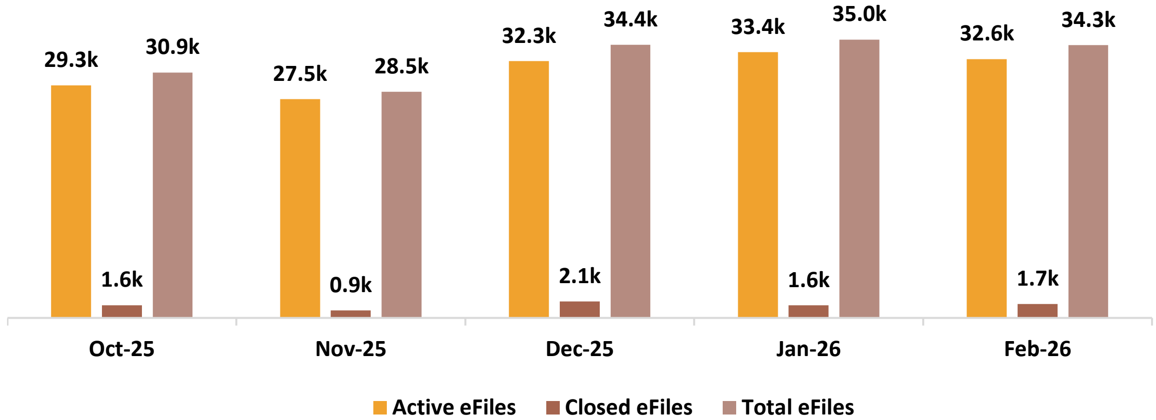

1 मुख्य-मुख्य बातें
फरवरी, 2026

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां (फरवरी 2026)

4,291
स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

16,34,141
वर्ग फुट स्थान खाली हुआ

92,62,15,608
कचरा निपटान से अर्जित राजस्व

III. लंबित मामलों में कमी

निपटान

- ✓ 4,81,540 लोक शिकायतें
- ✓ 22,880 लोक शिकायत अपीलें
- ✓ 1,045 संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र
- ✓ 724 राज्य सरकारों से प्राप्त पत्र
- ✓ 165 आईएमसी संदर्भ
- ✓ 388 पीएमओ से प्राप्त पत्र

पूरे किए गए संसदीय आश्वासन

83

रिकॉर्ड प्रबंधन

- ✓ 2,43,247 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई और 1,28,131 फिजिकल फाइलों की छंटाई की गई।

2 औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग)

मुख्य व्याख्या

केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजेक्शन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर फरवरी, 2026 में केवल 4.13 रह गया है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होगी और दक्षता बढ़ेगी।

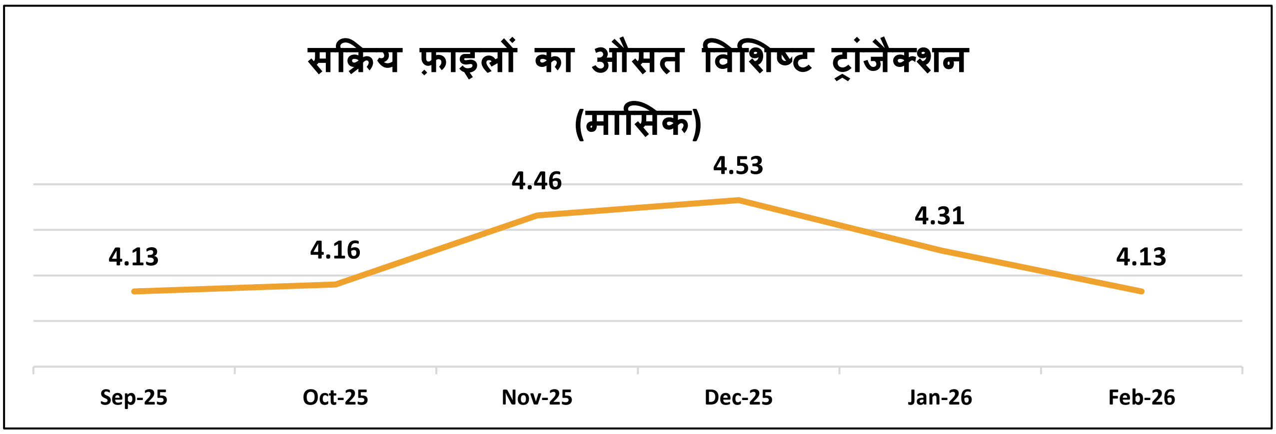

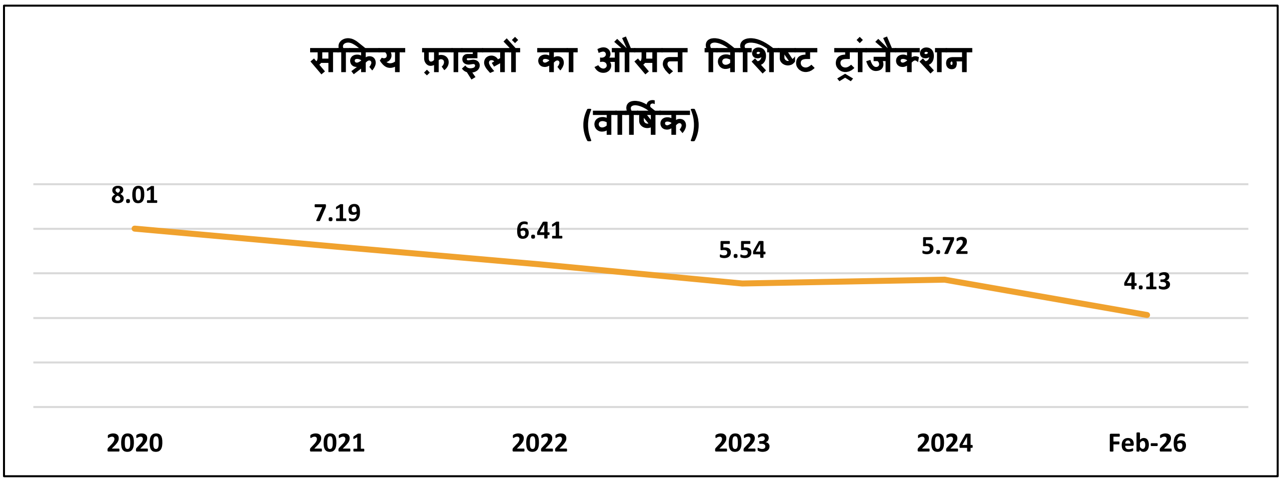

2.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (फरवरी 2026)

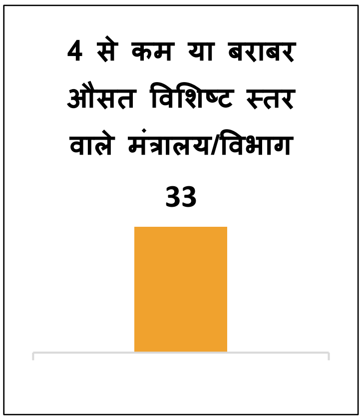

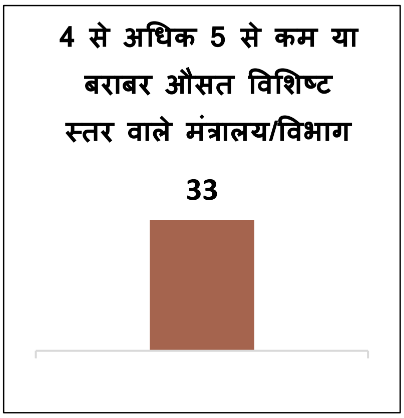

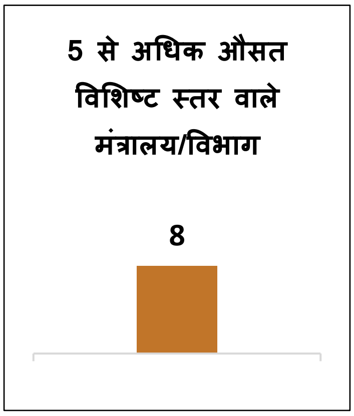

2.2. डिलेयरिंग की स्थिति

निम्नलिखित ग्राफ, फरवरी, 2026 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है:

क. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है

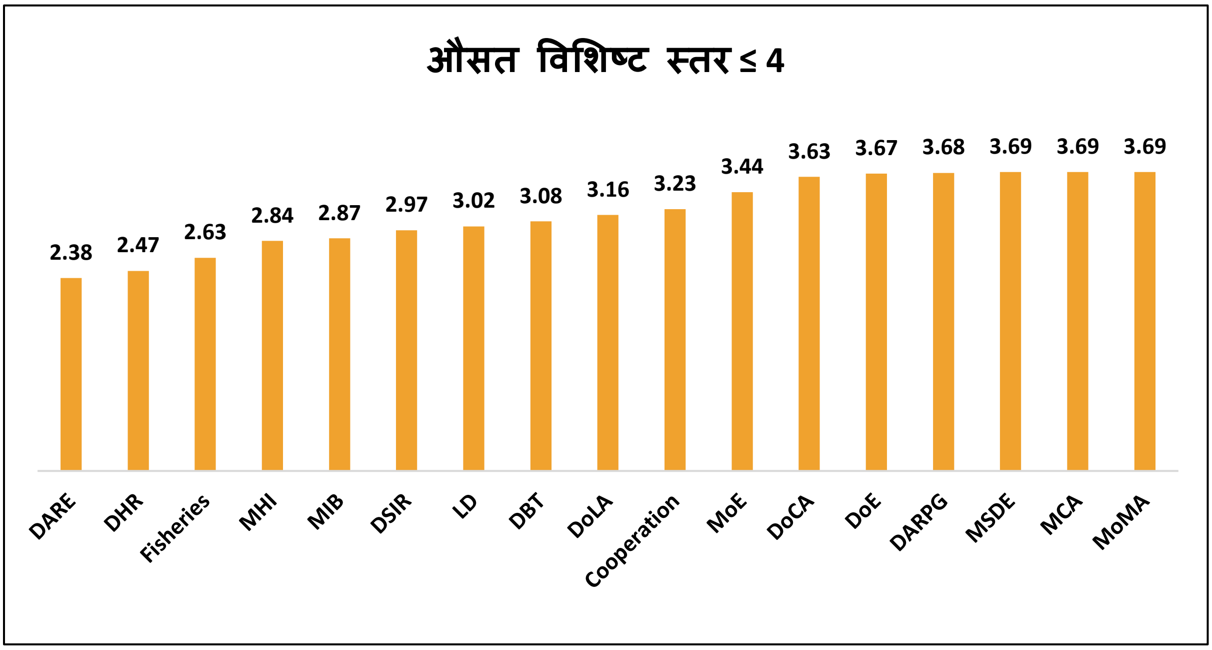

ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है (जारी..)

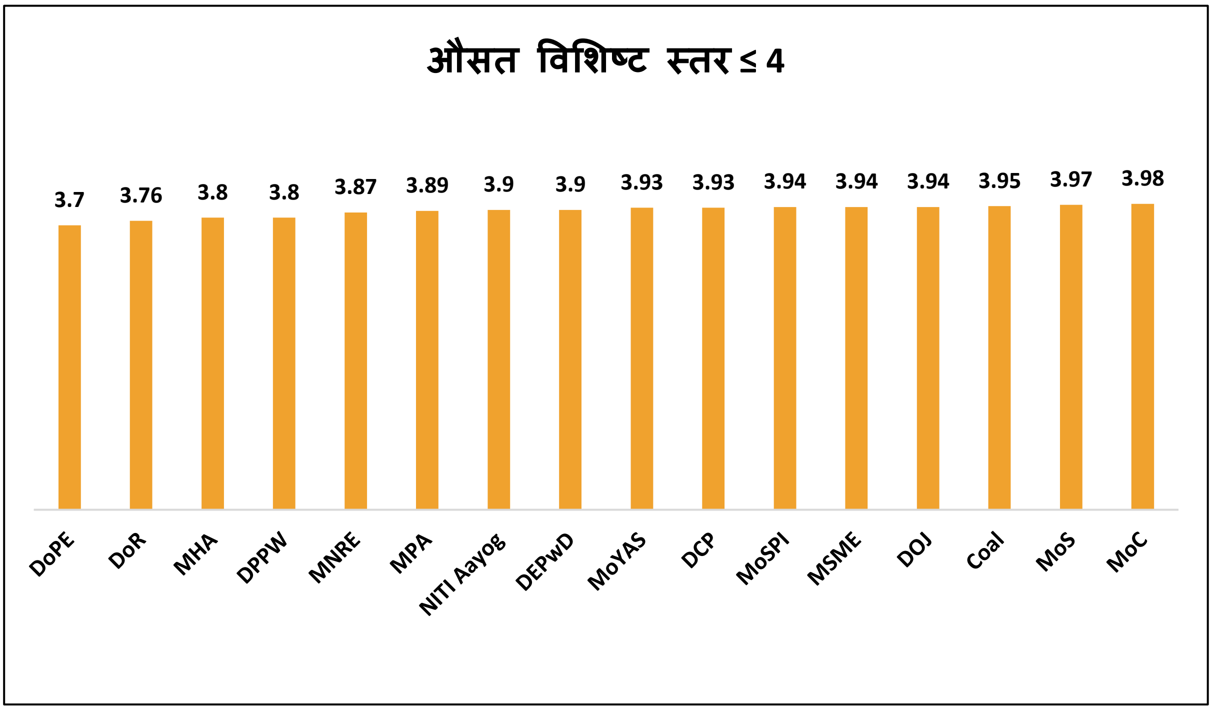

ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजेक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है

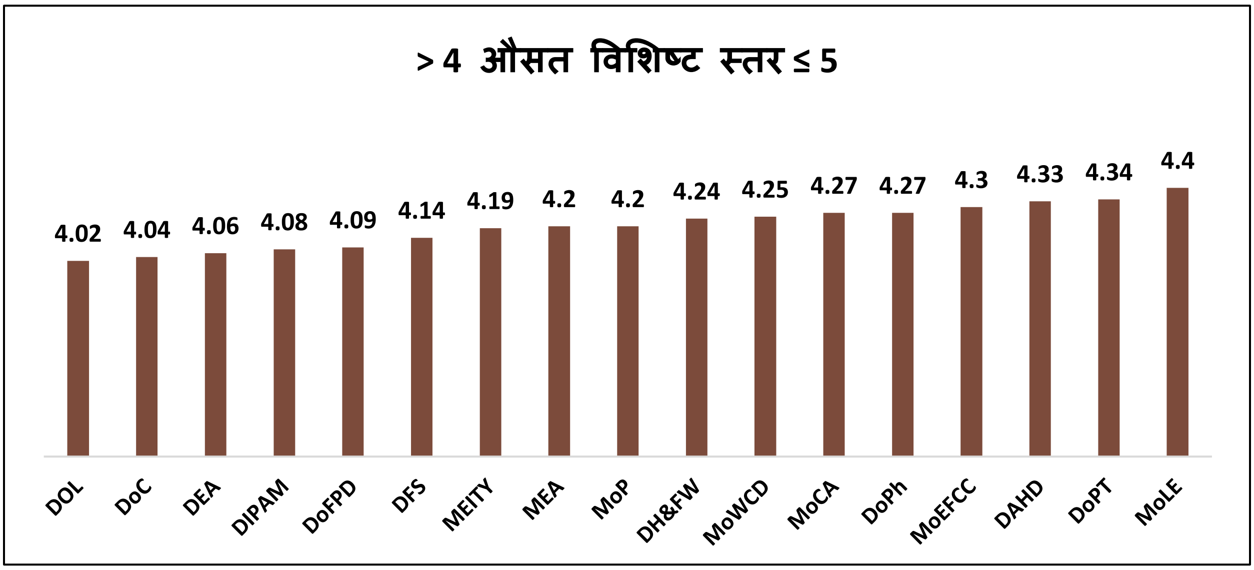

ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजेक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है (जारी...)

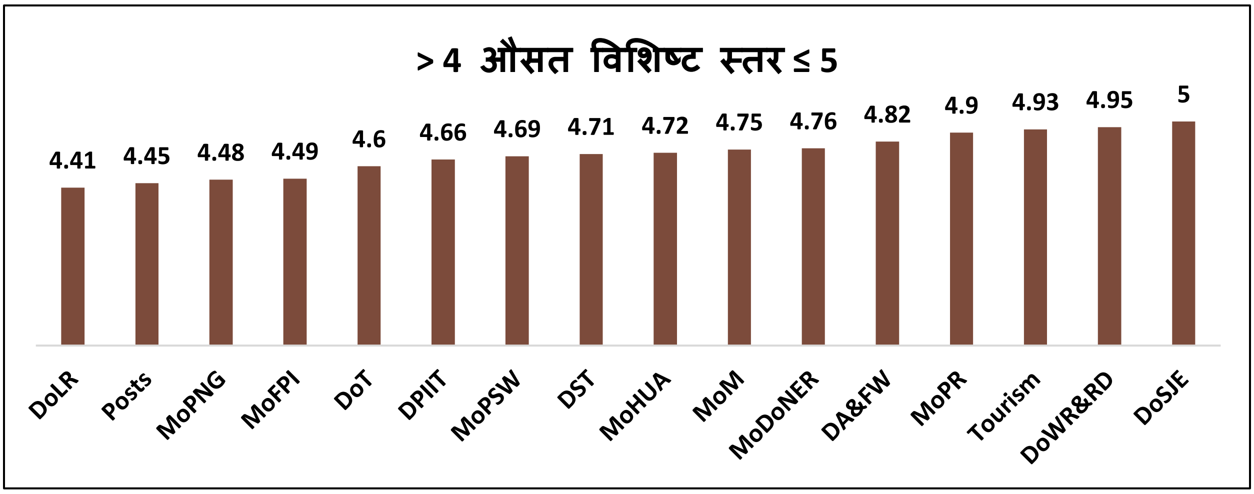

ग. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजेक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग

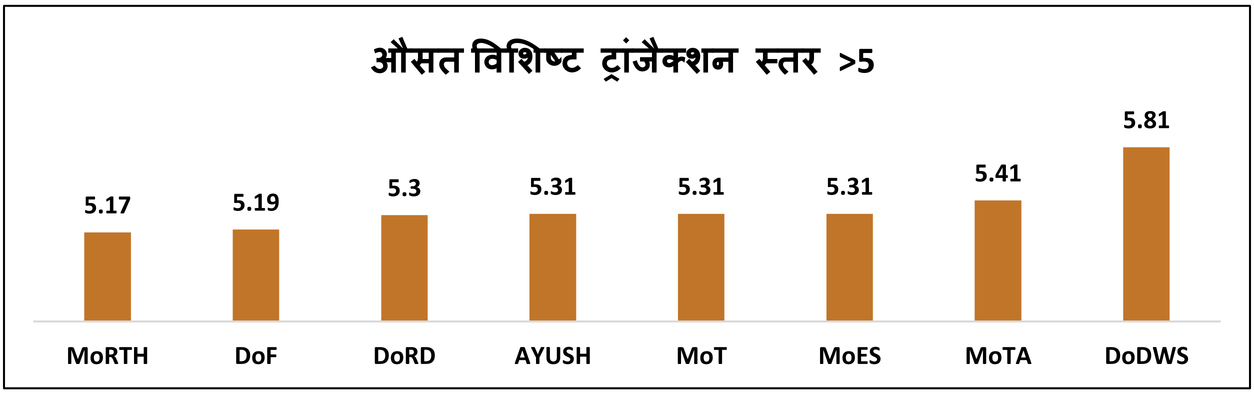

3 ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन

3.1 ई-ऑफिस विश्लेषण

➢ ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड (https://vishleshan.eoffice.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को किया गया ।

यह डैशबोर्ड निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- गहन डाटा विश्लेषण को आसान बनाने और निर्णयन प्रकिया को सदृढ़ करने के लिए रियल टाइम मीट्रिक्स।
- डाटा विजुअलाइज़ेशन और ट्रेंड के मूल्यांकन के माध्यम से निर्णयन प्रकिया में वृद्धि।
- ई-ऑफिस को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के डाटा विश्लेशष।
- आईईडीएम के प्रभावी तथा व्यापक कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

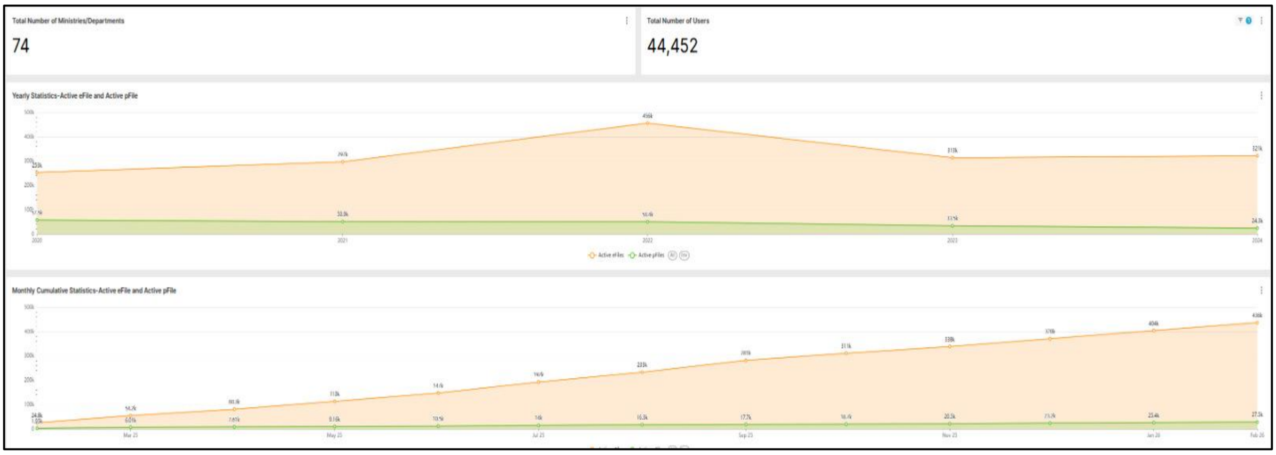

ई-ऑफिस विश्लेषण डैशबोर्ड इंटरफ़ेस

यूआरएल: https://vishleshan.eoffice.gov.in/

डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में यह भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (जिनके संबंध में केवल एनआईसी ईमेल और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ एनआईसी से विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) के लिए सुलभ है।

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी

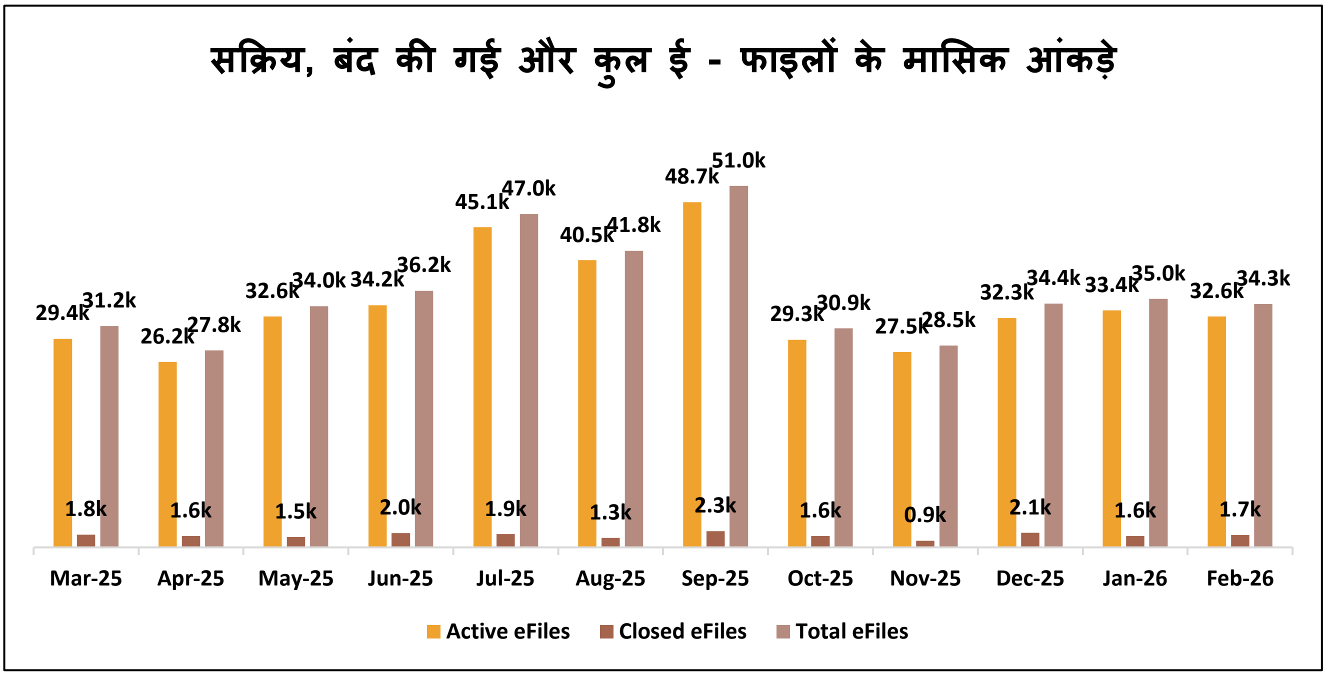

कुल ई-फाइलें मार्च, 2025 में **31.2 हजार** से फरवरी, 2026 में **34.3 हजार** तक पहुंच गई हैं। यह मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निरंतर अपनाए जाने और सक्रिय उपयोग को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय और बंद की गई फाइलों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है - जो ***बेहतर डिजिटल वर्कफ़्लो और फ़ाइल प्रबंधन को दर्शाता है।***

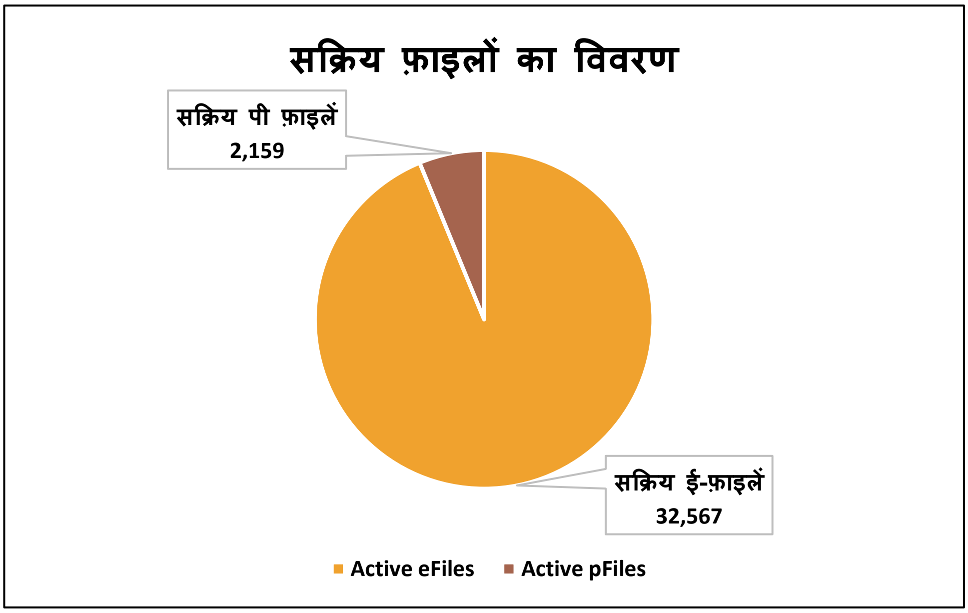

फरवरी, 2026 में कुल **सक्रिय फाइलों** में ई-फाइलों का हिस्सा **93.78%** था, जो फिजिकल फाइलों की तुलना में डिजिटल फाइलों के अधिक उपयोग को दर्शाता है।

3.3. ई-फ़ाइलों का सृजन

फरवरी, 2026 माह के लिए सक्रिय ई-फाइलों में <90 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले मंत्रालय/विभाग:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	ई फ़ाइलों का शेयर प्रतिशत
1	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	89.11%
2	डीओएचएफडब्ल्यू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	89.02%
3	दूरसंचार विभाग	86.51%
4	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	84.92%
5	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	81.66%
6	आयुष मंत्रालय	78.03%
7	गृह मंत्रालय	68.69%
8	राजभाषा विभाग	56.34%

3.4. अंतर-विभागीय फाइल संचलन

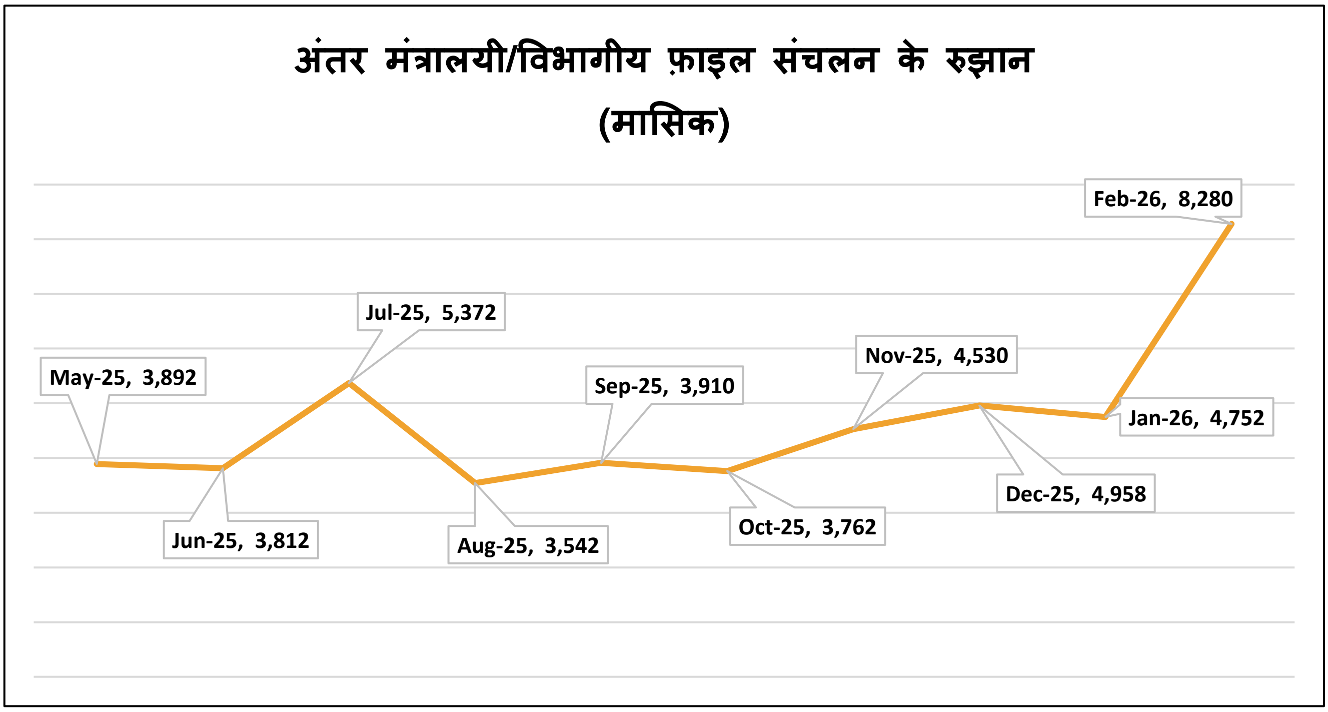

- **अंतर-मंत्रालयी फाइल संचलन में शीर्ष मंत्रालय/विभाग - फरवरी, 2026**

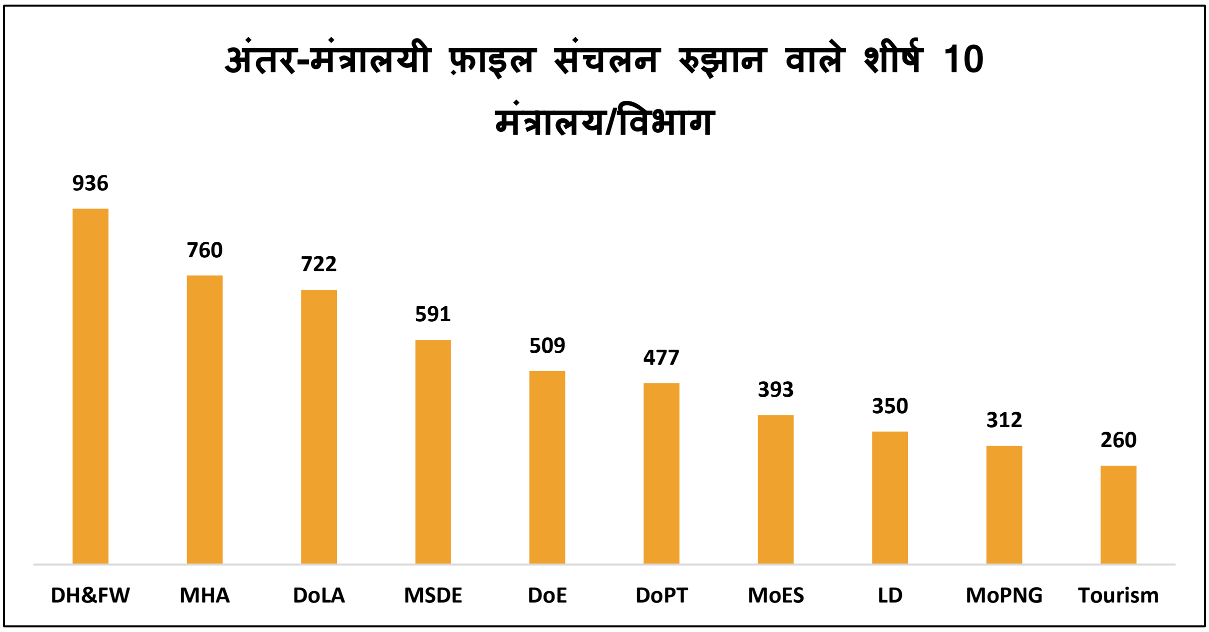

3.5. ई-रिसीट्स अपनाना (ई-रिसीट्स का % हिस्सा)

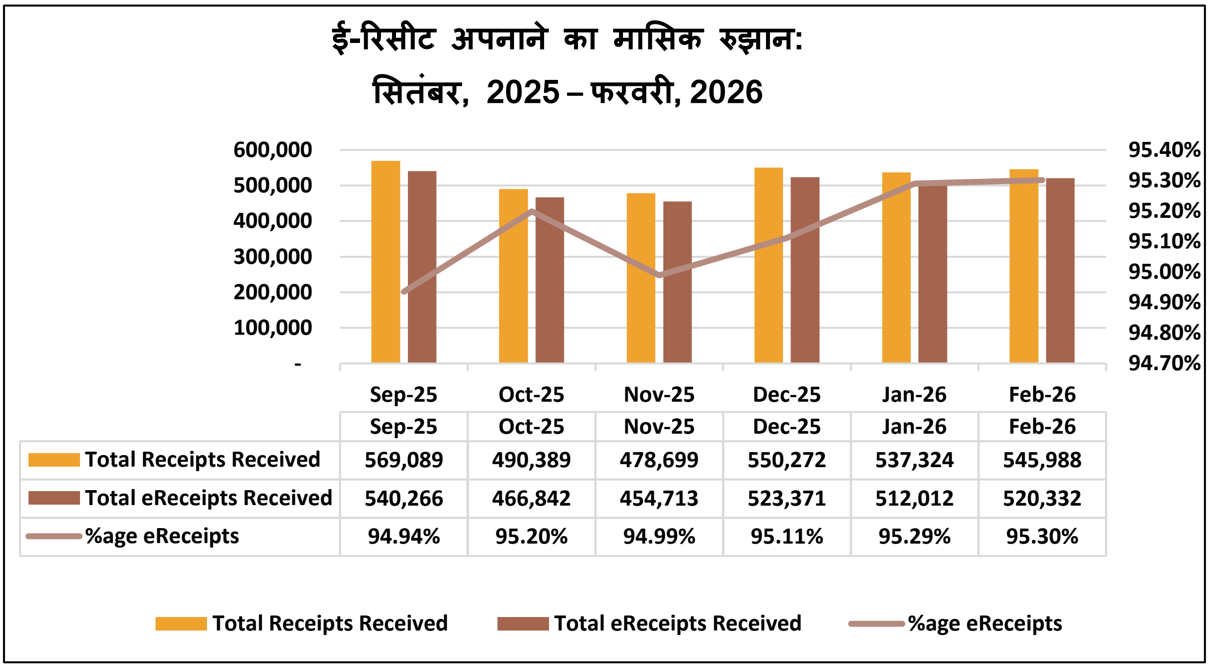

	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26
Total Receipts Received	569,089	490,389	478,699	550,272	537,324	545,988
Total eReceipts Received	540,266	466,842	454,713	523,371	512,012	520,332
%age eReceipts	94.94%	95.20%	94.99%	95.11%	95.29%	95.30%

पिछले छह महीनों में ई-रिसीट्स का शेयर लगातार 94% से ऊपर बना हुआ है, जो **फरवरी, 2026 में 95.30%** के उच्चतम स्तर पर है - यह मंत्रालयों/विभागों में रिसीट प्रबंधन में निरंतर डिजिटल अडॉप्शन का संकेत है।

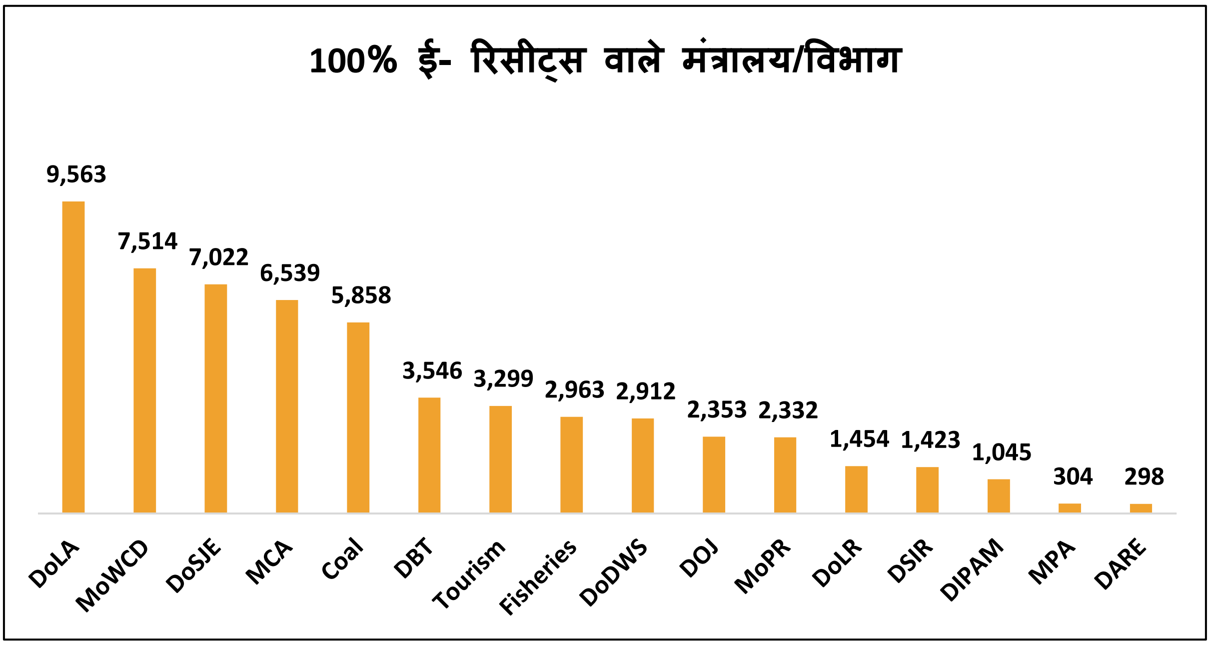

3.6. ई-ऑफिस विश्लेषण

फरवरी, 2026 माह का मंत्रालय-वार विश्लेषण संक्षेप में इस प्रकार है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
1	आर्थिक कार्य विभाग - वित्त मंत्रालय	96.87%	97.25%	37.59%
2	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	100.00%	99.09%	52.87%
3	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	96.67%	94.90%	32%
4	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	100.00%	100.00%	6.25%
5	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	84.92%	99.54%	50.44%
6	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	100.00%	99.82%	34.63%
7	बायो टेक्नोलॉजी विभाग	100.00%	100.00%	16%
8	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	100.00%	99.79%	33.33%
9	वाणिज्य विभाग	99.68%	98.31%	35.99%
10	उपभोक्ता कार्य विभाग	95.09%	99.87%	29.69%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
11	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	68.27%
12	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.97%	40%
13	उर्वरक विभाग	99.10%	99.83%	54.60%
14	मत्स्य पालन विभाग	99.38%	100.00%	10.53%
15	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	100.00%	99.57%	39.04%
16	न्याय विभाग	100.00%	100.00%	26.92%
17	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	100.00%	45.65%
18	विधि कार्य विभाग	100.00%	100.00%	10.56%
19	राजभाषा विभाग	56.34%	66.49%	40.63%
20	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	98.85%	33.33%
21	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	81.66%	89.25%	40.19%
22	औषध विभाग	100.00%	99.41%	44.90%
23	डाक विभाग	99.77%	99.75%	43.90%
24	लोक उद्यम विभाग	100.00%	99.85%	26.09%
25	ग्रामीण विकास विभाग	100.00%	99.96%	61.13%
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	100.00%	99.95%	49.46%
27	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	15.38%
28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	51.94%
29	दूरसंचार विभाग	86.51%	89.86%	45.91%
30	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संवर्धन विभाग	98.90%	99.99%	54.79%
31	डीएफएस - वित्त मंत्रालय	98.15%	94.06%	40.68%
32	डीएचआर विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	96.67%	84.06%	6.85%
33	डीआईपीएएम - वित्त मंत्रालय	100.00%	100.00%	50%
34	डीओई - वित्त मंत्रालय	93.84%	72.26%	23.71%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
35	डीओएचएफडब्ल्यू विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	89.02%	94.18%	41.31%
36	डीओआर - वित्त मंत्रालय	95.60%	91.73%	29.24%
37	विधायी विभाग	100.00%	99.90%	14.53%
38	आयुष मंत्रालय	78.03%	77.92%	67.39%
39	नागर विमानन मंत्रालय	95.36%	99.88%	46.49%
40	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	38.31%
41	सहकारिता मंत्रालय	98.58%	94.61%	17.58%
42	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	33.82%
43	संस्कृति मंत्रालय	95.98%	96.51%	43.08%
44	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	99.36%	99.97%	45.35%
45	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	99.87%	52.94%
46	शिक्षा मंत्रालय	93.04%	97.74%	31.33%
47	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	98.99%	95.65%	35.46%
48	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	91.19%	99.96%	35.32%
49	विदेश मंत्रालय	99.72%	99.72%	33.84%
50	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	94.20%	54.33%
51	भारी उद्योग मंत्रालय	99.23%	99.81%	17.39%
52	गृह मंत्रालय	68.69%	77.30%	30.70%
53	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	98.25%	98.90%	48.07%
54	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	99.10%	96.01%	18.22%
55	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	89.11%	85.37%	48.37%
56	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	100.00%	88.88%	40%
57	खान मंत्रालय	99.51%	99.95%	44.44%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
58	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	94.39%	94.16%	28%
59	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	98.77%	99.95%	34.92%
60	पंचायती राज मंत्रालय	100.00%	100.00%	51.38%
61	संसदीय कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	33.33%
62	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	97.39%	98.99%	50%
63	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	99.68%	99.92%	48.48%
64	विद्युत मंत्रालय	98.11%	99.97%	44.58%
65	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.98%	52.19%
66	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	99.75%	93.91%	31.01%
67	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	100.00%	99.74%	30.41%
68	इस्पात मंत्रालय	100.00%	96.03%	30.11%
69	वस्त्र मंत्रालय	99.53%	77.88%	63.25%
70	पर्यटन मंत्रालय	100.00%	100.00%	57.14%
71	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00%	99.26%	69.05%
72	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	100.00%	40.26%
73	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	98.34%	99.42%	39.85%
74	नीति आयोग	99.78%	98.38%	33.10%

जिन मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है, उनके द्वारा डिलेयरिंग/डेलिगेशन की समीक्षा की जानी है।

4 विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना

कुल उपलब्धियां (वर्ष 2021 – फरवरी, 2026)

मापदंड	एससी1.0 - एससी4.0	दिसंबर'24- अगस्त'25	एससी 5.0	दिसंबर'25 - फरवरी '26	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)	2,364.05	1,007.1	833.92	292.83	**4,497.9**
खाली हुआ स्थान (लाख वर्ग फुट में)	643.82	57.23	233.75	40.99	**975.79**
स्वच्छता अभियान स्थल	11,49,935	60,442	11,59,783	11,259	**23,81,419**
फाइलों की छंटाई (लाख में)	131.4	6.81	29.52	4.30	**172.03**

आँकड़े विशेष अभियानों **(एस.सी. 1.0 - एस.सी. 5.0)** और सचिवालय सुधारों की निरंतर गति को दर्शाते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। फरवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, कुल उपलब्धियों में शामिल हैं: स्क्रैप निपटान से **₹4,497.9 करोड़** की आय हुई, **975.79 लाख वर्ग फुट** कार्यालय स्थान खाली हुआ, **23.81 लाख से ज़्यादा स्थलों को** स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत लाया गया और **172.03 लाख फाइलों का निपटान किया गया।** निरंतर प्रगति, स्वच्छता के संस्थागतकरण और दैनिक शासन में दक्षता-उन्मुख परिपाटियों की पुष्टि करती है।

4.1. कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)

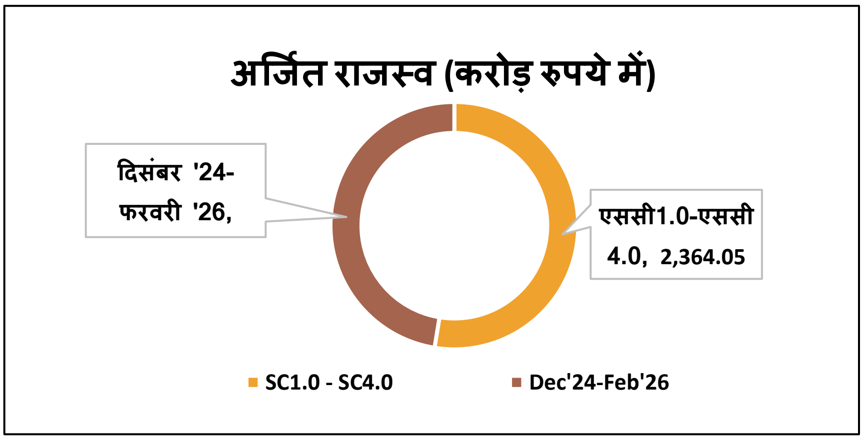

कचरा निपटान के माध्यम से अर्जित कुल **₹4,497.9 करोड़** राजस्व में से, **₹2,364.05 करोड़** का राजस्व, **विशेष अभियान 1.0 और विशेष अभियान 4.0** के दौरान प्राप्त हुआ। यह गति **दिसंबर, 2024 से अगस्त, 2025 में 1007.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के साथ जारी रही, इसके बाद ₹833.92** करोड़ का राजस्व, **विशेष अभियान 5.0** के दौरान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, कचरा निपटान से **दिसंबर, 2025 और जनवरी 2026 के दौरान**, **292.83** करोड़ रु. राजस्व के रूप में प्राप्त हुए जो विशेष अभियानों के सभी चरणों में निरंतर राजस्व सृजन को दर्शाता है।

4.2. कचरा निपटान से अर्जित राजस्व (फ़रवरी, 2026)

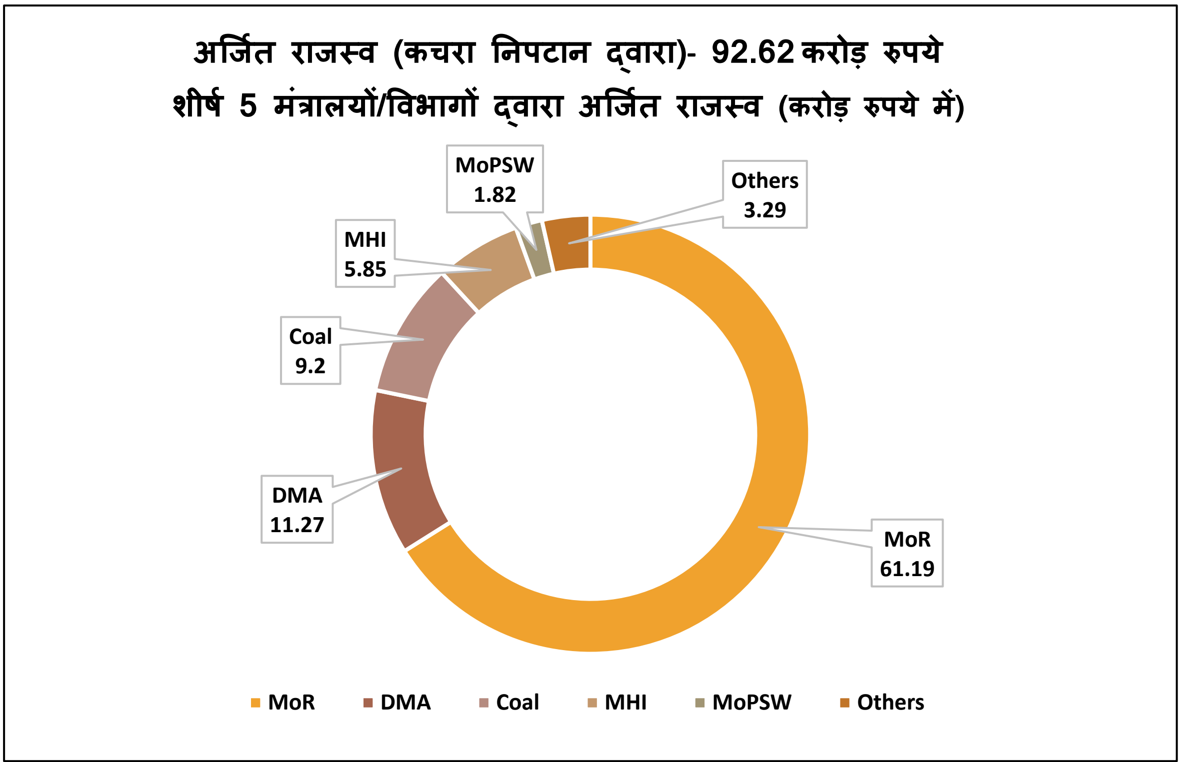

4.3. खाली हुआ स्थान (फरवरी 2026)

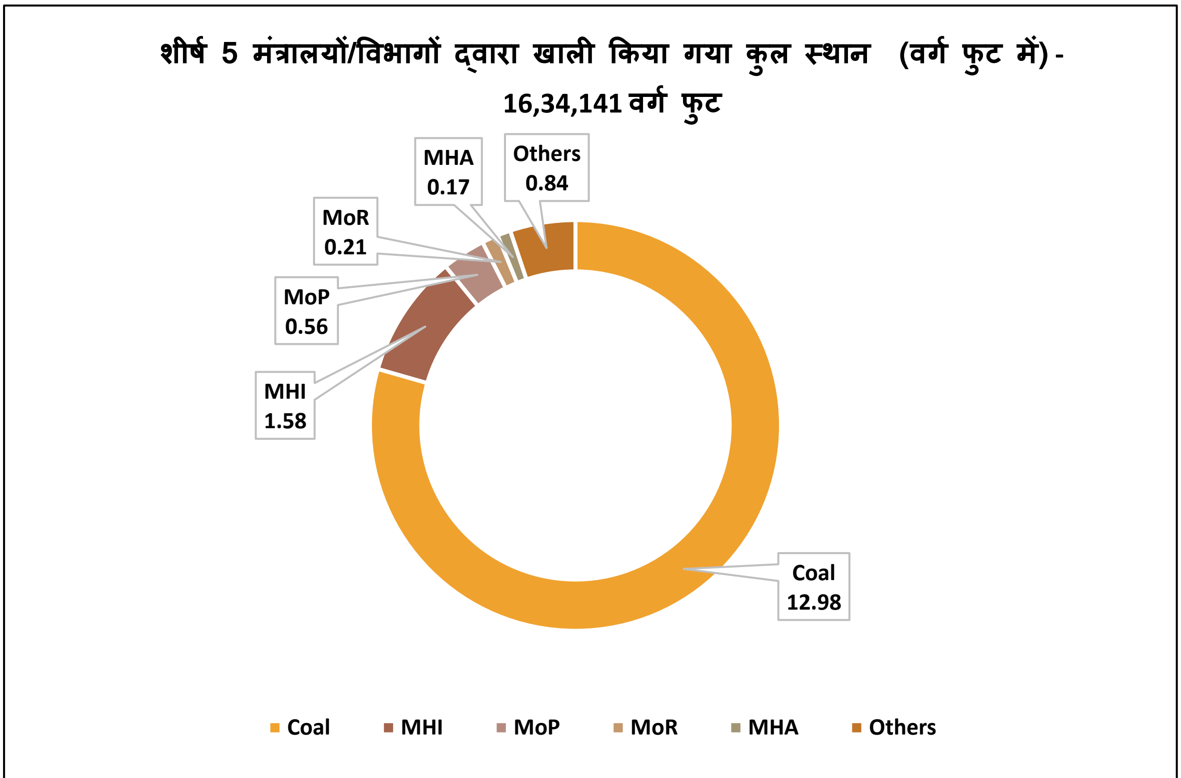

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली हुआ स्थान

- **कोयला मंत्रालय:** फरवरी, 2026 में कुल 12,98,377 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	साइट/संगठन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	10,99,739.04
2.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	95,478
3.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	16,221.54

- **भारी उद्योग मंत्रालय:** फरवरी, 2026 में कुल 1,58,241 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	साइट/संगठन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1,21,450
2.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स	11,500
3.	ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर	10,000

- **रेल मंत्रालय:** फरवरी, 2026 में कुल 21,147 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	ज़ोन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	पूर्व मध्य रेल	7,250
2.	उत्तर-पश्चिम रेल	3,809
3.	पश्चिम मध्य रेल	2,616

4.4. स्वच्छता अभियान स्थल (फरवरी, 2026)

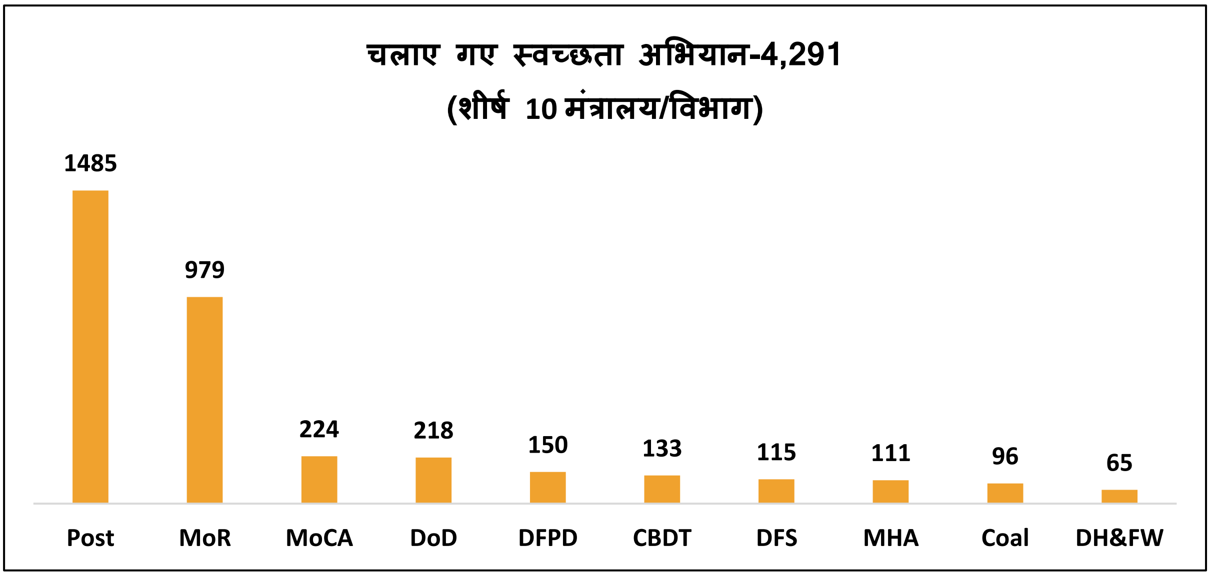

चलाए गए कुल **4,291** स्वच्छता अभियानों में से, अकेले **डाक विभाग ने कुल अभियानों का लगभग 34.61 प्रतिशत अभियान चलाया**, इसके बाद रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय इत्यादि का स्थान है, जो इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वच्छता पहलों में मजबूत और निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

4.5. छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (फरवरी, 2026)

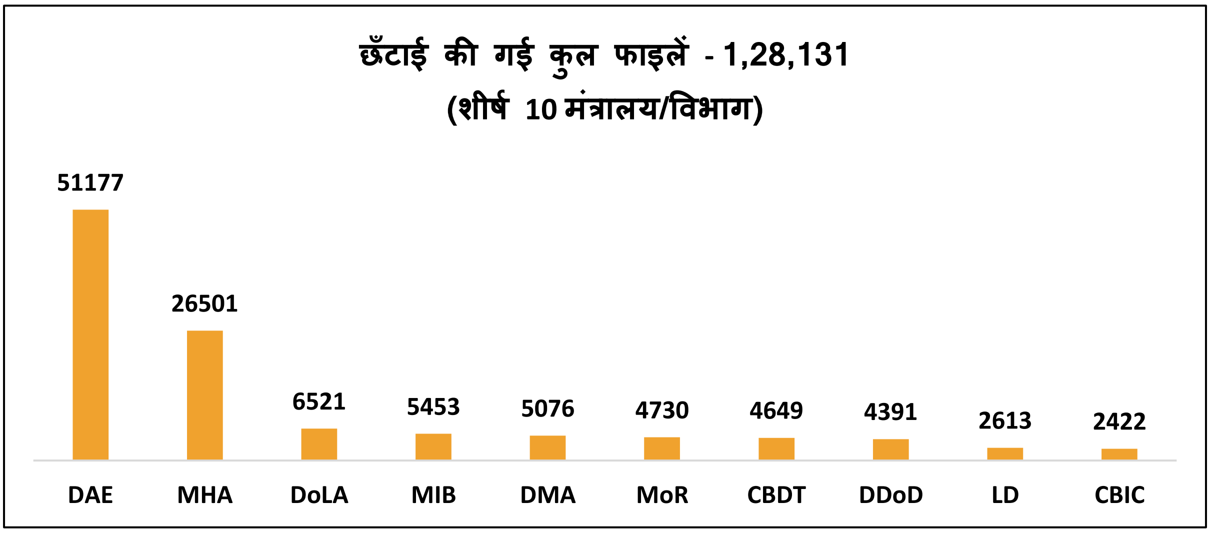

छंटाई/बंद की गई **1,28,131** फाइलों में से, **परमाणु ऊर्जा विभाग** ने **51,177** फाइलों की छँटाई करके पहला स्थान प्राप्त किया, इसके बाद **गृह मंत्रालय और विधि कार्य विभाग** का स्थान रहा जहाँ क्रमशः**26,501** और **6,521 फ़ाइलों** की छँटाई की गई। यह दर्शाता है कि प्रमुख मंत्रालय, अव्यवस्था को दूर करने और फाइल प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं।

5 पहले - बाद में

मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए सचित्र साक्ष्य- फरवरी- 2026

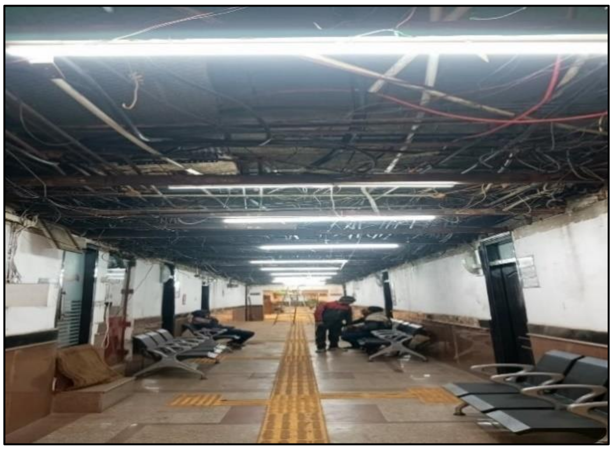
पहले

बाद में

केंद्रीय राजस्व भवन, प्रधान आयकर कार्यालय, दिल्ली में गलियारे के क्षेत्र का रूपांतरण;
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)

पहले

बाद में

अव्यवस्थित स्थान को स्वच्छ कार्यालय कार्यस्थल में परिवर्तित किया गया, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता; **परमाणु ऊर्जा विभाग**

पहले

बाद में

एनएलसीआईएल में धातु अपशिष्ट का निपटान; **कोयला मंत्रालय**

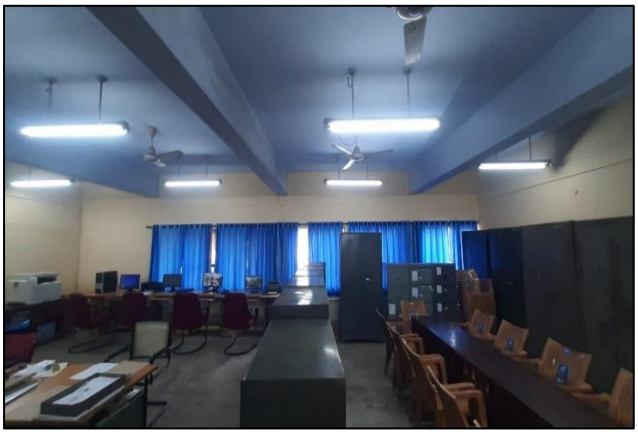

पहले बाद में

पुराने रिकॉर्डों को हटाने से अव्यवस्थित कार्यालय का स्थान, स्वच्छ और व्यवस्थित कार्य वातावरण में परिवर्तित हो गया; **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम मंत्रालय**

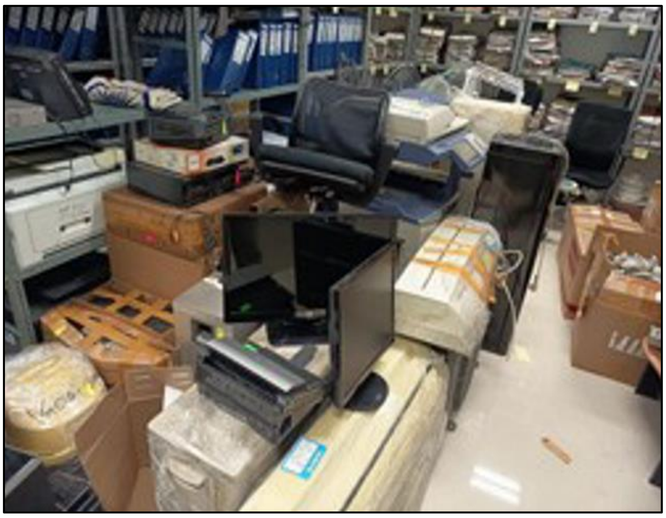

पहले बाद में

इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित ईओआई में पुराने ई-कचरे का निपटान किया गया; **विदेश मंत्रालय**

पहले बाद में

सीआरआई, कसौली में स्वच्छता अभियान चलाया गया; **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

6 कार्यालय स्थान में वृद्धि

मुंबई स्थित न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की दीवारों का सौंदर्यीकरण; **परमाणु ऊर्जा विभाग**

सीजीएचएस आयुष गांधीनगर में कार्यालय पार्किंग की जगह को बेहतर बनाने के लिए फर्श बिछाया गया; **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में पुराने गोदाम को कार्यस्थल में परिवर्तित किया गया; **वाणिज्य विभाग**

7 मंत्रालयों/विभागों का मापदंड-वार कार्य-निष्पादन

क. फरवरी, 2026 में निपटान के आधार पर शीर्ष 5 मंत्रालय/विभाग

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

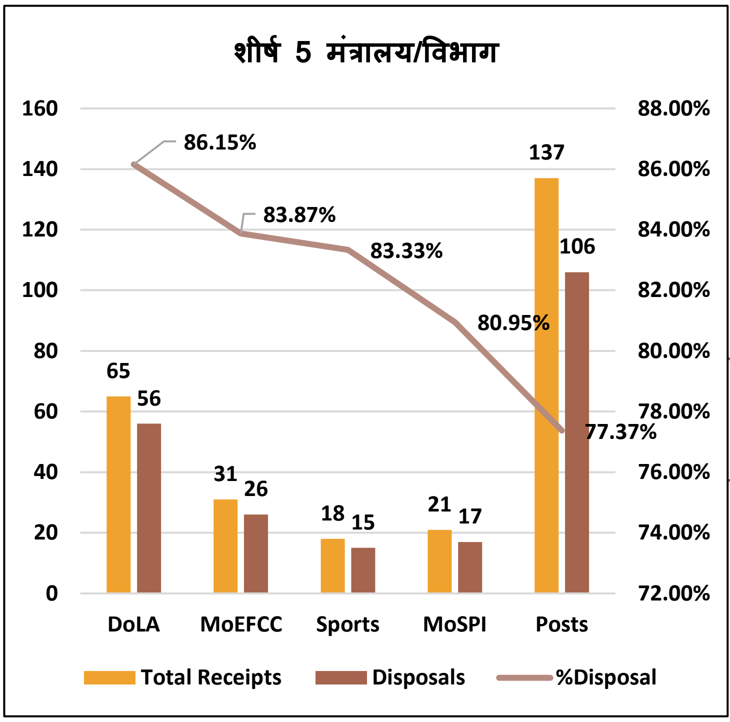

संसदीय आश्वासन

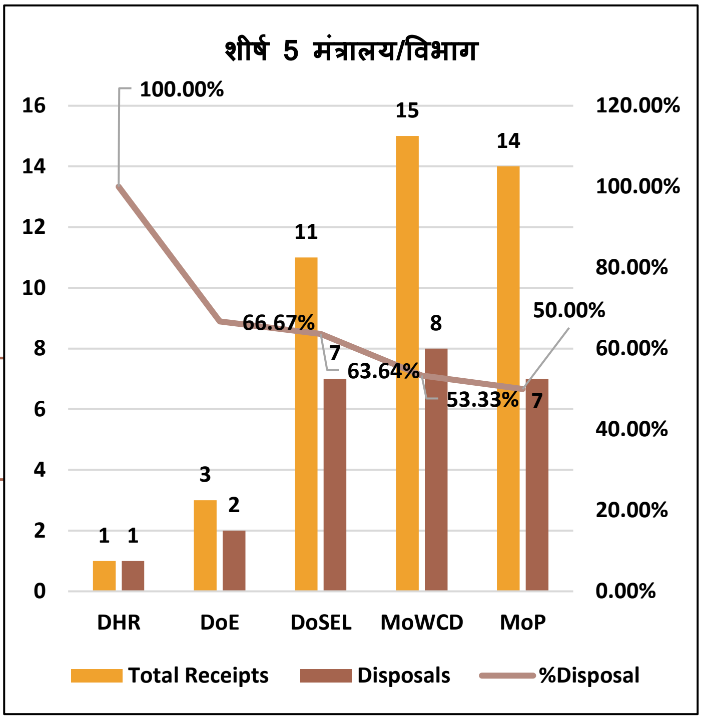

आईएमसी संदर्भ

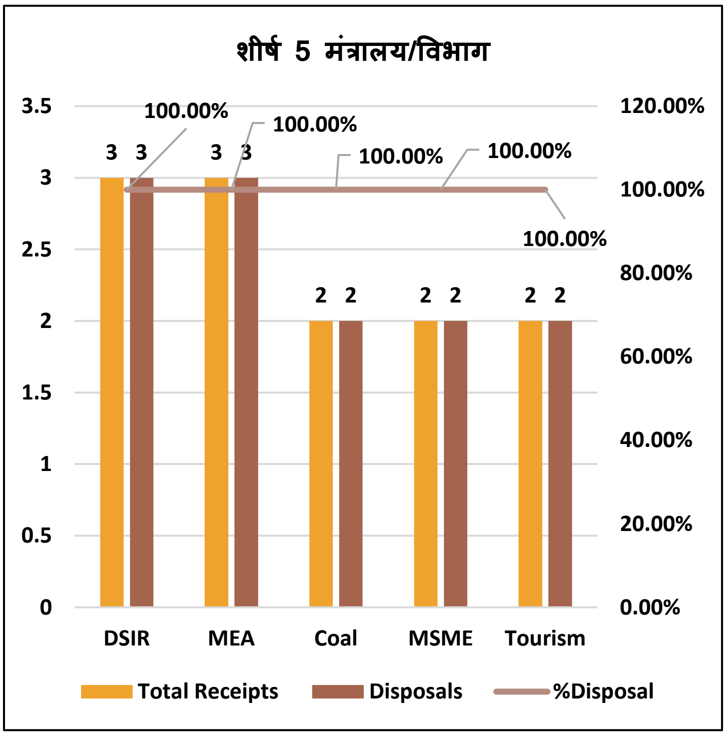

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र

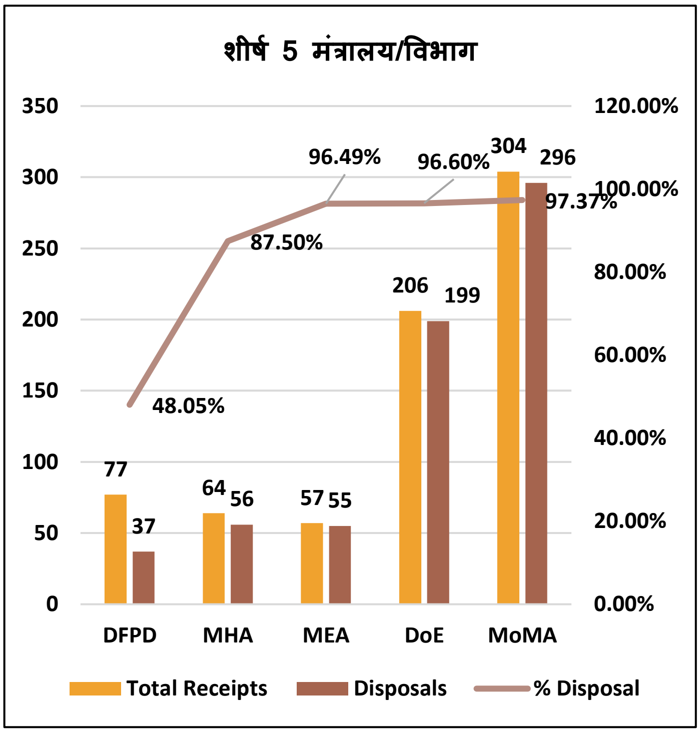

पीएमओ से प्राप्त पत्र

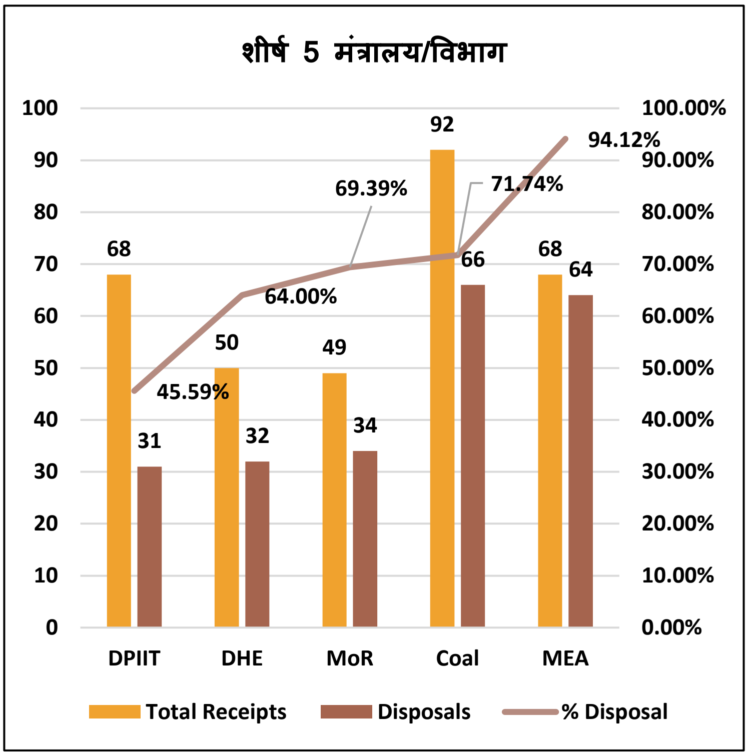

लोक शिकायत

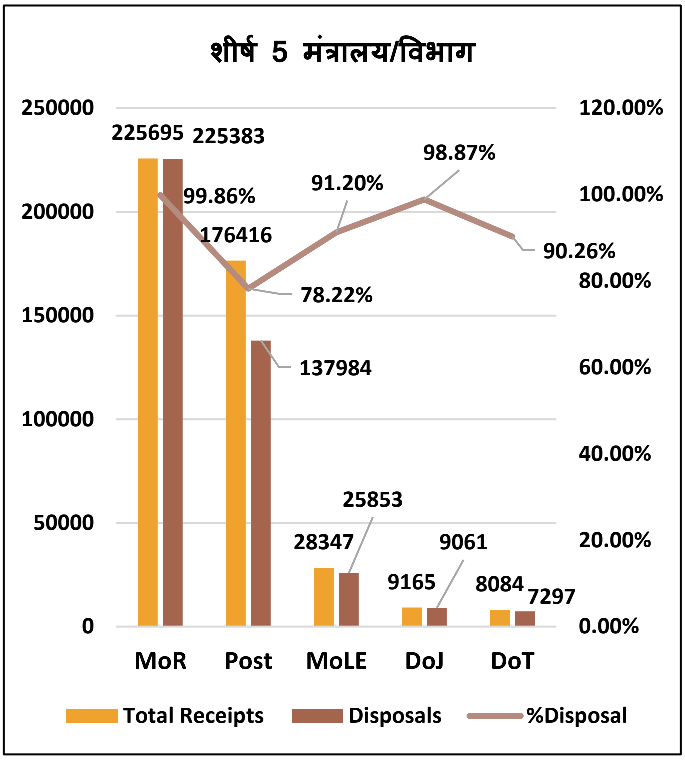

छंटाई की गई फाइलें

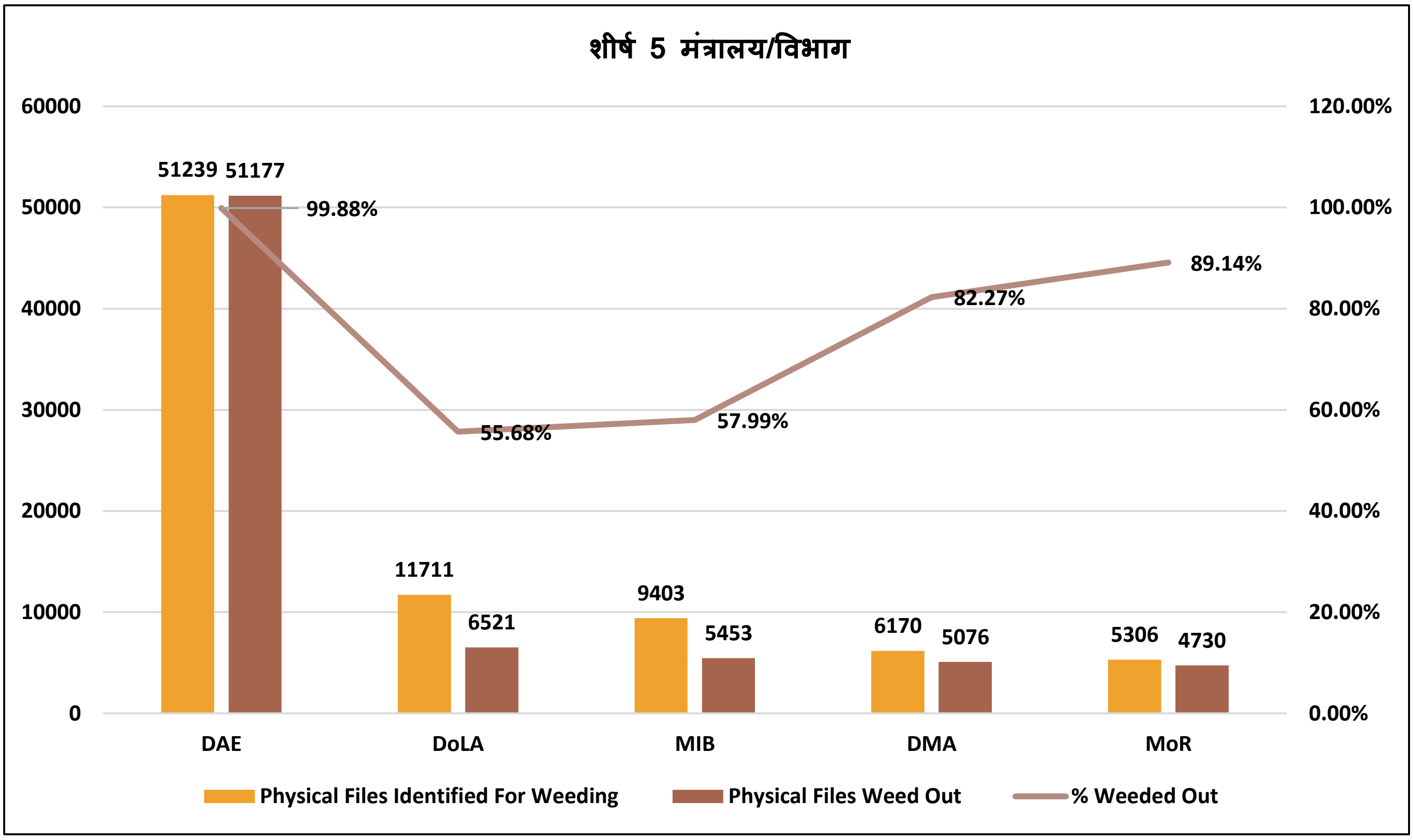

8 इन फोकस: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

परिचय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने शिकायत निवारण, अभिलेख प्रबंधन और स्वच्छता पर केंद्रित विशेष अभियान 5.0 (2-31 अक्टूबर 2025) कार्यान्वित किया। डीओपीटी ने 157 अभियान स्थलों पर अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें 1,851 शिकायतें, 13 संसद सदस्य संदर्भ और 9 पीएमओ संदर्भों का निपटान किया गया। अभियान के दौरान, 1,10,474 फिजिकल फाइलों और 1,25,651 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 96,767 फिजिकल फ़ाइलों की छँटाई की गई और 76,344 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। इन प्रयासों से 11,753 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ और ₹33.15 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

8.1. कार्यालय स्थान का कुशल प्रबंधन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यालय स्थान के कुशल प्रबंधन और इष्टतम उपयोग के लिए की गई पहलों को आगे बढ़ाते हुए, समीक्षा और युक्तिकरण हेतु एक व्यापक अभ्यास किया गया। कार्यालय स्थान के व्यवस्थित पुनर्आवंटन और समेकन, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अनुपयोगी फर्नीचर, अनुपयोगी उपकरण और फाइलों की छँटाई करके, विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के दौरान 11,753 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली किया।

स्वच्छता की झलकियां

लोधी कॉलोनी पार्क, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान

8.2. कचरा निपटान

विशेष अभियान 5.0 के दौरान, विभाग ने मुख्यालय, संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में स्क्रैप के निपटान और बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने के लिए लक्षित पहल की। इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभाग ने अभियान के दौरान ₹33.15 लाख का राजस्व अर्जित किया।

सीआईसी भवन, नई दिल्ली में अनुपयोगी और अव्यवस्थित जगह को साफ-सुथरे क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।

8.3. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ

केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, डीओपीटी ने **गृह कल्याण केंद्र, लोधी रोड** में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।

सीबीआई एसीबी कोचीन, केरल में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया

सीबीआई, एसटीबी, मुंबई शाखा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया

पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के तहत **सीएटी, पीबी, नई दिल्ली** में एंटी-स्मॉग गन स्थापित की गई।

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली स्थित विभाग के अभिलेख कक्ष की सफाई।

8.4. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना

1. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)

यूपीएससी ने 2025 में एक नया एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आधार-आधारित केवाईसी सत्यापन और डिजिलॉकर दस्तावेज़ अपलोड को एकीकृत किया गया है, साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 'पसंदीदा केंद्र' की गारंटीकृत सुविधा भी प्रदान की गई है।

2. ई-डोजियर

एसएससी ने ई-डॉक्यूमेंट पोर्टल के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों को उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट भेजने की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ कर दिया है, जिससे पहले वाली फिजिकल डॉक्यूमेंट की प्रणाली समाप्त हो गई है।

3. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संबंधी संकलन

केंद्र सरकार की सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, रियायतें और छूटों पर एक संशोधित संकलन 25 दिसंबर 2025 को एक समेकित संदर्भ दस्तावेज के रूप में जारी किया गया था।

4. भविष्य और पीएफएमएस के साथ ईएचआरएमएस 2.0 का एकीकरण

ईएचआरएमएस 2.0 के एकीकरण से पेंशन प्रपत्रों में सेवा अभिलेखों का स्वतः भरा जाना, ऑर्गनोग्राम मॉड्यूल के माध्यम से संगठनात्मक पदानुक्रमों का विज़ुअलाइजेशन और पीएफएमएस के माध्यम से दावों की त्वरित प्रतिपूर्ति जैसे कार्यों को किया जा सकेगा।

5. एआई-संचालित भर्ती नियम जनरेटर टूल

विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करने में मंत्रालयों और विभागों की सहायता के लिए 25 दिसंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया।

6. आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में सुधार

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को अप्रैल 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के ऐपकोएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया था, जिससे पहली अपील के डेटा का स्वचालित अंतरण और दूसरी अपीलों का तेजी से निपटान संभव हो सका।

8.5. उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

1. रोजगार मेला

अब तक **18** राष्ट्रीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों पर युवाओं को शामिल होने के लिए **11.60** लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

2. प्रतिभा -सेतु पोर्टल

यूपीएससी ने जुलाई 2025 में प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न चरणों को उत्तीर्ण करने वाले उन उम्मीदवारों के विवरण और परीक्षा स्कोर साझा करना था, जिनका चयन नहीं हो पाया था। इससे निजी और सार्वजनिक नियोक्ताओं को उन्हें भर्ती के लिए विचार करने में मदद मिली। **15** फरवरी **2026** तक, पोर्टल के माध्यम से **610** पंजीकृत उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

3. आईगॉट कर्मयोगी

मार्च **2026** तक की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर लगभग **1.51** करोड़ उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं, जहाँ **4,300** से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एआई आधारित टूल जैसे एआई सारथी - इंटेलिजेंट कोर्स डिस्कवरी असिस्टेंट और आईगॉट एआई ट्यूटर - इन-कोर्स कन्वर्सेशनल लर्निंग कंपेनियन को लॉन्च किया जा चुका है। एआई आधारित अनुवाद और सबटाइटलिंग की सुविधा के साथ, आईगॉट पाठ्यक्रम अब **11** प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

9. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D.O. No. 502/2/2/2021-CA.V

27th November, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, many initiatives have been undertaken in the recent years to make governance more responsive, accountable and transparent. The initiative for Increasing Efficiency in Decision Making, implemented since 2021, is a step in the same direction. It aims at achieving flatter and leaner organizational structures by putting in place appropriate delegation at various levels, rationalizing workload, thereby speeding up decision-making while increasing the productivity and efficiency of officers.

2. These measures have been incorporated into the Central Secretariat Manual of Office Procedure, 2022 wherein, it is emphasized that, each Ministry/Department will review the instructions on levels of disposal and channel of submission, keeping the number of levels to the minimum by delegating powers to lower formations. To facilitate quicker decision-making, the channels of submission should not be more than four.

3. However, it is observed that delayering is not being implemented in true spirit and a trend of increasing the channels of submission is observed in some Ministries/Departments. This is against the essence of the reforms undertaken so far and creates potential delays in file processing.

4. To sustain the measures undertaken as a part of Increasing Efficiency in Decision Making, you are advised to review the levels of disposal and channel of submission in your Ministry/Department and ensure that the levels do not exceed four and that the Special Secretary/ Additional Secretary/ Joint Secretary function independently as bureau heads.

5. I request you to devote your personal attention to this matter and ensure that these measures are implemented in letter and spirit, thereby fostering speedy and efficient decision making in Government.

With best wishes,

Yours sincerely,

(T.V. Somanathan)

To,

All Secretaries to Government of India

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel.: 011-23016696, 23011241 Fax : 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in

10. स्वच्छता और लंबित मामलों के त्वरित निपटान पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-11011/01/2025-O&M-DARPG (e-9571)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated: December 26, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Efforts aimed at Swachhata and expeditious disposal of pending matters in Government.

The Special Campaign 5.0 focussing on Swachhata and expeditious disposal of pending matters was conducted from October 2 – 31, 2025 by all Ministries /Departments. In order to institutionalise and sustain the momentum generated Ministries/Departments are requested to continue the following actions:

(i) System of Nodal Officers and Special Campaign Portal will continue. Nodal Officers to oversee institutionalisation/continuation of activities aimed at Swachhata and reducing pendency. Nodal Officers to also update the progress on the Portal,

(ii) Ministries/Departments may dedicate 3 hours every week for the activities as mentioned on the Portal (**www.scdpm.nic.in**), and

(iii) Nodal Officers may review the progress of activities on a weekly basis and the Secretary of the Ministry/Department are requested to review the progress on a monthly basis.

This issues with the approval of competent authority.

26/12/25

(Sarita Chauhan)
Joint Secretary to Government of India

To
All Secretaries to the Government of India

Copy- All Nodal Officers of Special Campaign 5.0

11. ई ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

MOST IMPORTANT

No O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938)
Government of India
Ministry of Personnel Pensions and Public Grievances
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

6th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan
Janpath, New Delhi

Dated 17th January 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: eOffice Analytics - regarding.

*****

The undersigned is directed to say that the following guidelines may be adopted by Ministries / Departments for implementation of eOffice in Central Secretariat:

(i) Display their standing orders of delayering/Channels of Submission on their respective e-Office dashboard

(ii) Review Virtual Private Network (VPN) usage. Non-users may be identified and steps may be taken to deactivate / close the idle account after due examination and process. The NIC teams of Ministries/Departments may approach NIC VPN Division to obtain VPN data and for deactivation of idle VPN accounts

(iii) Follow the Manual of Office Procedure strictly and to avoid proliferation of part-files on the same subject. 'Common office function codes' as prescribed in Chapter - 6 'File Management System' of CSMOP 2022 are to be followed at the time of opening a new eFile in eOffice

(iv) Use of Knowledge Management System (KMS) for managing the OM's Circulars, Orders etc. and further adding them as references in eFiles. Further, a list of all files (Division-wise/bureau-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files

(v) Review the Designation Master in Personal Information Management System (PIMS) and identify the designations related to Personal Staff of officers. Based on the list of designations received from the Ministries / Departments, personal staff of Officers will be removed from the counts of distinct levels so that the actual distinct levels may be captured and reflected on the Analytics Dashboard

(vi) Review and examine the Distinct Levels. Ministries/Departments may refer to 'e-File Movement Status' Report under the 'Data Analytics' tab in the e-File MIS Reports application

Contd

11. ई ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

-2-

(vii) Review the Basic File Head and notify the standardized Heads based on the relevant subjects of the Ministry/Department. Based on the list of Heads received from the Ministries/Departments, a consolidated list of Heads will be prepared which may be considered as standard Subjects to fetch the Subject-wise pendency.

(viii) The Ministries/Departments who process statutory clearance for various projects such as Ministry of Environment, Forest and Climate Change may provide expected time for clearance, so that the processing time of such files may be noticed.

(ix) E-Office Analytics to be developed to indicate file pendency at each level, to identify time delays and pendency. Emphasis to be given to identifying subject specific pendency across Ministries/Departments.

2. This issues with the approval of Secretary, DARPG.

(Sunil K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.011-23440371
email: sunilk.singh73@nic.in

To

Secretaries to the Govt. of India

Copy to:

1. DG, NIC
2. Shri M.K. Mishra, DDG, NIC email: mk.mishra@nic.in
3. Shri Kapil Kumar Sharma, Sr. Director (IT), NIC
4. eOffice-PMU, NIC

Copy for information to:

PSO to Secy. (AR&PG)/PA to JS (SC) /DS (eOffice)

अनुलग्नक I: अपलोड नहीं किए गए आँकड़े

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
1	राजस्व विभाग
2	युवा कार्यक्रम विभाग
3	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
6	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
8	पंचायती राज मंत्रालय
9	वस्त्र मंत्रालय
10	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संक्षेपाक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
6.	डीए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
11.	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग
24.	डीओएफपीडी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग
30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट्स	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यूआर एंड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
49.	डीओवाईए	युवा कार्यक्रम विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	एमओसीए	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	डीओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.	माइटी	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
81.	एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज़्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
88.	एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईएस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001